RAJYA SABHA

Friday the 24th February 1989/5th Phalguna, 1910 (Saka)

The House met at eleven of the clock **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

असम को विशेष कृषि अनुदान

*41. **श्रीमती विजया चक्रवर्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम सरकार ने पिछली बाढ़ के दौरान हुए भारी नुकसान को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से विशेष कृषि अनुदान के लिए अनुरोध किया था, और

(ख) यदि हां, तो असम के लिए अब तक स्वीकृत की गई कृषि अनुदान की कुल धनराशि कितनी है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी हां, असम राज्य सरकार ने 1988 की बाढ़ों के संबंध में प्रस्तुत किये गये अपने ज्ञापन में कृषि आदान, राजसहायता और बालू हटाने के लिए 14.58 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की थी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने छोटे तथा सीमान्त किसानों के खेती वाले प्रभावित क्षेत्र के लिये कृषि आदान राज सहायता तथा बालू को हटाने हेतु 5.85 करोड़ रुपये की अधिकतम व्यय की मंजूरी दी है ।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, what the Government of Assam has asked for is a moderate amount. It is only **Rs. 14.58 crores** and the ceiling of expenditure approved by the Government, as the Minister has just now stated, is only Rs. 5.85 crores. Last year's unprecedented floods caused colossal loss to agriculture in Assam, the like of which was never witnessed during the last 80 years. The exchequer of Assam came under constraints due to relief, rehabilitation and repair works spread over almost all the districts of Assam. Against this background, a major agricutural grant is an imperative necessity to save Assam from an imminent food crisis. So, what special help, in the form of grant for pesticides, seeds, mechanized farming, etc., is the Government envisaging to grant to the State of Assam, apart from the amount sanctioned already?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या बहिन जी को आंकड़े बताते हुए मुझे खुशी होगी और थोड़ा सा खेद भी होगा । खेद इसलिये होगा कि जब आसाम में बाढ़ आई तो फौरी तौर पर वहां पर हमारे स्टेट मिनिस्टर गए, मैं गया, प्रधान मंत्री जी गये और कोई ज्ञापन दिए बिना 40 करोड़ रुपया हमने उनको फौरी तौर पर सहायता के रूप में दिए कि वहां पर काम शुरू किया जाए । हमने वहां पर 40 करोड़ रुपये दिए । टोटल से फलड के लिये आसाम को 85.38 करोड़ रुपये मंजूर किए गए और सभापति महोदय जी आसाम ने खर्च किए वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल से 38 करोड़ रुपये खर्च किए 24 जनवरी, 1989 तक यह कहते हैं कि पैसा और दें । इन्होंने अभी तक उसका हिसाब नहीं दिया बार-बार हमारे कहने के बाद इतना ही जवाब भेजा कि आपने 85 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, उनमें से 38 करोड़ रुपये खर्च किए है। बाढ़ पर नियंत्रण के लिये हमने उनको दिए 28.29 करोड़ रुपये और इन्होंने खर्च किए सिर्फ 3 करोड़ रुपये अर्थात् 28 में से 3 करोड़ रुपये और 85 में से 38 करोड़ रुपये । अब यदि वे भारत सरकार को यह कहें कि पैसा कम दिया है तो यह मुनासिब बात नहीं होगी ।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: That is not the point, I think. How is it possible? When the State is reeling under flood for long nine months, how is it possible that **they**

are spending only Rs. 3 lakhs? It is practically impossible. Moreover, I think, it is the plea of the Minister concerned to deprive the State because I know, Sir, and you also know it that during crisis situations like drought or earthquake or flood Central assistance in liberal form has been granted. Assam's economy is based on agriculture. The hon. Minister has also visited the State during floods. But his plea is of not giving the entire expenditure—what it is called actually I do not know—on the materials spent. Still, I want to know from the Minister, apart from all these things, what is actually the basis of Rs. 5.85 crores that has been granted to Assam. Secondly, I want to know whether this amount is reasonable for a State whose agricultural land in 17 districts out of 18 districts is covered by sand and whether the Minister concerned is considering giving a reasonable amount. Apart from all the explanation that the Minister has just now offered, I want to know whether he is considering granting any reasonable amount to avert the crisis that sand has created in the agricultural land of the 17 districts of the State.

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, आप जानते है कि बाढ़ हो चाहे सूखा हो, उसका बाकायदा नार्म बना हुआ है । उसमें कुछ 100 प्रतिशत सहायता होती है, कुछ 75 प्रतिशत सहायता होती है, कुछ 50 प्रतिशत सहायता होती है । अनाज की शक्ल में अलग से दिया जाता है । 25 हजार टन चावल दिया गया था असम को । उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि ज्यों ही असम अवर्नमेंट का ज्ञापन हमारे पास आया, असम गवर्नमेंट ने जो ज्ञापन दिया, वह दिया 19 सितम्बर को । बाढ़ वहां ठीक है चार बार आई, और जो आखिरी बाढ़ थी, वह काफी भयंकर थी । हमने जाकर मौका भी देखा । लेकिन ज्यों ही 19 तारीख को ज्ञापन हमारे पास आया, तो 20 तारीख को ही हमने केन्द्रीय दल बना दिया और 25 तारीख को, यानि एक हफ्ते के अन्दर ही केन्द्रीय दल असम में पहंच गया और जाकर के उन्होंने एक एक बात को देखा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 85 करोड़ रुपये असम को देना चाहिये, फौरन 85 करोड़ दे दिया, जिसमें से उन्होंने जो खर्च किया वह हमने बताया । जहां तक ताल्लुक है बाल हटाने का, असम गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपया मांगा और हमने 46 लाख रुपया दिया, यानि मांग 20 की थी और हमने दिया 46 लाख रुपया और 85 करोड़ में से खर्च ये 38 करोड़ रुपये करें, यह बात मुनासिब नहीं है । मैं बहन जी से इतनी ही बात कहना कि मेहरबानी करके वे वहां की स्टेट गवर्नमेंट को परस्यू करें कि जो पैसा भारत सरकार ने आपको दिया है वह ठीक काम पर खर्च करें ताकि आइन्दा वहां बाढ़ न आ सके । और अगर आप हर तरह से कहें कि किस किस चीज के लिये दिया है तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि किस किस काम के लिये दिया है, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। मेरे पास यह सारे आंकड़े मौजूद है ।

SHRI SUNIL BASU RAY: My question is: What is the date on which the money was sent to the Government, and what is the period that the Minister is referring to, for which the money was spent? After the receipt of that information which he has given here, has he got any other information from the Assam Government or not?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, जैसा मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि असम गवर्नमेंट ने ज्यों ही ज्ञापन भेजा उसी दिन टीम बना दी हमने और जहां तक पैसा देने का ताल्लुक है प्रधान मंत्री जी स्वंय वहां पर गए.. (**व्यवधान**) ....

श्री जसवंत सिंह: आप तारीख बता दीजिए.... (**व्यवधान**) ....

श्री भजन लाल : मैं तारीख बताने जा रहा हूं आपको, जरा सुनने की कृपा करेंगे तभी काम चलेगा न । 16 अक्तूबर को प्रधान मंत्री जी गए, उन्होंने वहां एलान कर दिया मौके पर, 40 करोड़ रुपये देने का ... (व्यवधान) ...

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: The flood started in the month of April, and the Prime Minister visited in October.

श्री भजन लाल: सभापति जी, इनके पास बाकायदा मार्जिनल मनी होती है, 7 करोड़ 25 लाख रुपया इनके पास मार्जिनल मनी है ।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: I am sorry to hear the answer of the Minister. A State which is reeling under floods for nine months...

SHRI SUNIL BASU RAY: Unfortunately the Minister does not know anything about that State.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: As regards the Central assistance to the State of Assam, it is mentioned in the answer of the hon. Minister that the demand from the State Government was Rs. 14.58 crores whereas the Centre approved Rs. 5.85 crores. Every year about eighteen States are getting affected by some calamity or the other like floods, cyclones, or droughts and unnecessarily this question is made a matter of dispute between the Union Government and the State Governments. The State Governments naturally demand more and the Central Government takes its own time in finalising the allotment.

MR. CHAIRMAN: Kindly put your question.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: The States charge that the Central Government allots a small part of the amount demanded and it takes a lot of time before releasing the funds allotted.

MR. CHAIRMAN: You put your question.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: The Congress people who lost power in the States now ruled by the non-Congress (I) State Governments criticise that the funds are being diverted. These things are not desirable and they affected the Centre-State relations. So, instead of the State Government sending the report, the Central Government taking its own time and alloting a small quantum of it and the State Government not being able to finish the work before March, why not the Central Government take over the entire activities, because more than half of the population in about eighteen States are affected every year? It is no longer a regional problem. It is a national problem. So, let the nation come to the rescue of the affected persons. My point is, why not the Central Government think over this matter and see that the Central Government takes up the calamity relief measures at the national scale instead of leaving the burden on the State Governments?

MR. CHAIRMAN: Will the State Governments agree to the Government of India going and doing the work there? No State will agree.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Let the Central Government take up the entire burden of undertaking the relief.

MR. CHAIRMAN: No State will agree if the Government of India goes and works there.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: He said the Centre must come to the rescue of the States so far as finances are concerned. That is important.

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, यह तो ठीक बात है कि मुल्क के बहुत से हिस्सों में बाढ़ आती है, सूखा भी पड़ा है पिछले तीन चार सालों से बाढ़ और सूखे तथा बाढ़ में जितनी मदद भारत सरकार ने पिछले दो सालों में दी है उतनी पहले कभी नहीं दी ।

SHRI VIRENDRA VERMA: Sir, the reply should be short and specific.

MR. CHAIRMAN: The question is long and you want a short reply.

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि जिससे बाढ़ न आए आप जानते हैं कि जितना नुकसान होता है वह ब्रहमपुत्र की वजह से होता है । ब्रह्मपुत्र में पानी ज्यादा आने की वजह से बाढ़ आती है। आप समझने की कृपा कीजिए। इन्होंने कहा कि मंत्री जी को कुछ आता नहीं है : इनको पता नहीं है कि जितना पोलिटिकल ज्ञान इनका है उतना तो मैं जेब में फालतू रखता हूं . . . (**व्यवधान**) . . .

MR. CHAIRMAN: Please don't; interrupt.

श्री भजन लाल : लेकिन अफसोस की बात है कि पुराने मैम्बर भी ऐसी बात कहते हैं । बड़ी मुश्किल से इन्होंने राज्य सभा देख ली। आइंदा पता लगेगा दुबारा चुनकर आओगे तब । हमारा बहुत पुराना तजुर्बा है ।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: We did not come to Rajya Sabha by high jacking the entire legislature party. We came to Rajya Sabha on our own right.

श्री भजन लाल : आपने जो बात कही उसका जवाब तो दे देना ही चाहिये। (**व्यवधान**) आप जो कहेंगे उसका जवाब हमको देना होगा । (**व्यवधान**) मैंने यह कहा कि ब्रहमपुत्र के लिये असम गवर्नमेंट को पहले से कहा था कि आप इसके नियंत्रण के लिये इंतजाम करिये और जो इसके बैंक्स है उनको मजबूत करिये। असम गवर्नमेंट ने पिछले दो साल से एक पैसा भी ब्रहमपुत्र के दोनों तरफ जो बैंक्स है उनको ठीक करने पर खर्च नहीं किया । कसूर स्टेट गवर्नमेंट का है और दोष भारत सरकार पर लगाते हैं । काम खुद नहीं करते (**व्यवधान**) . . .

MR. CHAIRMAN: He is talking about Assam. The question is about Assam.

SHRI CHATURANAN MISHRA: The Minister has referred to all India floods.

MR. CHAIRMAN: The question is not on all-India floods.

SHRI CHATURANAN MISHRA: His reply was...

MR. CHAIRMAN: The question is limited to Assam.

SHRI DIPEN GHOSH: His supplementary was in a general form. The Minister is expected to reply to his supplementary. अगर वह जनरल सवाल पूछ रहे है तो मिनिस्टर साहब को जवाब दे देना चाहिये। यह असम पर जवाब दे रहे है. . . (**व्यवधान**) . . .

MR. CHAIRMAN: In his supplementary when he was going out of it I was trying to check him.

श्री जसवंत सिंह : अगर यह सवाल नहीं है तो यह जवाब कैसे दे रहे हैं . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सभापति : वह असम के बारे में जवाब दे रहे है । (**व्यवधान**)

You are an old Member and you know that supplementary arises out of the question, Q. No. 42.

*42. [The Questioner Shri V. Narayanasamy) was absent. For answer vide cos....29-39 infra.]

Import of steel

*43. SHRI DIPEN GHOSH:†
SHRI M. A. BABY:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government propose to import over 1.6 million tonnes of steel to meet the gap between its demand and supply for this year; and

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Dipen Ghosh.